Subsidy Portion of Loans

1617. SHRI S. M1ADHAVAN; Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether Government are aware of the fact that the subsidy portion of loans given like IRDP loans has not reached the beneficiaries in full; and

(b) whether this quantum of subsidy would be adjusted towards the interest charged for these loans so that the entire benefit would go to the beneficiaries?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT (SHRI UTTAMBHAI H. PATEL): (a) Government are aware that in a programme of the size of IRDP being implemented in all thS blocks of the country there could be some leakages in administration of subsidy to beneficiaries.

(b) In order to reduce leakages in the administration of subsidy under IRDP various alternatives to the capital subsidy have been considered from time to time. One of the alternatives suggested was the complete replacement of capital subsidy by interest subsidy. This was considered by the High Level Credit Committee, Conference of State Ministers of Rural Development, State Bank of India and the National Institute of Rural Development. All these discussions and studies did not favour the replacement of capital subsidy by interest subsidy.

उत्तर प्रदेश में ग्रामीण विकास परियोजनायें

1618 श्री ईश दत्त यादव : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में ग्रामीण विकास परियोजनाओं का जिलावार ब्यौरा क्या है ;

(ख) सरकार द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान तथा चालू वर्ष में प्रत्येक परियोजना के लिए वर्षवार कितनी धनराशि का आवंटन किया गया है ;

(ग) उत्तर प्रदेश के वे जिले कौन-कौन से हैं जहां ये परियोजनाएं समयानुसार कार्यान्वित नहीं हो रही हैं ; और

(घ) सरकार इन परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिये क्या कदम उठाने का विचार रखती है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई एच० पटेल) : (क) उत्तर प्रदेश में कार्यान्वित की जा रही ग्रामीण विकास परियोजनाओं के ब्यौरे निम्नलिखित है :—

कार्यक्रम का नाम	कवर किये गये जिले
1. समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आई० आर०डी०पी०)	कार्यक्रम राज्य के सभी जिलों/खण्डों में कार्यान्वित किया जा रहा है ।
2. जवाहर रोजगार योजना (जे०आर०वाई०) कार्यक्रम	के अन्तर्गत जिला/गांव स्तर पर शुरू की गई ग्रामीण विकास परियोजनाओं की केन्द्रीय स्तर पर निगरानी नहीं की जाती है । योजना के कार्यान्वयन की निगरानी राज्य स्तर पर सृजित किये गये रोजगार के श्रम दिनों के रूप में ही की जाती है ।